जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोन:- 230200, 230400 फैक्स:- 07469-230600 वर्ष: 17 संख्या: 227 प्रभात हिण्डौन सिटी, शनिवार 21 जून, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राहुल गांधी, अब देश का प्रधानमंत्री बनने को तैयार ही नहीं, तत्पर हैं

पहली बार वे अपने जन्म दिन, 19 जून को आयोजित ''फंक्शन'' में भाग लेने, 18 जून की रात को भारत लौट आए

- आज से पहले राहुल का जन्म दिवस, एक प्राइवेट मामला होता था तथा 19 जून को प्रायः विदेश में रहते थे, शायद आम कार्यकर्ता से मिलने से कतराने के कारण।
- पर, अब यह हिचकिचाहट खत्म हो गई है तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचित कर दिया गया था कि दोपहर में दो बजे राहुल एआईसीसी में आयेंगे, जन्म दिन पर उनके अभिवादन स्वीकार करने।
- पहली बार राहुल के जन्म दिवस पर दिल्ली के प्रमुख अखबारों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन छपे, राहुल गांधी को जन्म दिन की बधाई देते हुए।
- राहुल गांधी में यह परिवर्तन तब से आया है, जब से वे संसद में ''लीडर ऑफ ऑपोज़िशन'' (विपक्ष के नेता) बने हैं तथा इस पद से जुड़ी गरिमा, प्रतिष्ठा व अधिकार से काफी प्रभावित हुए हैं तथा जिस प्रकार का रोब, रूतबा व महत्व मोदी को मिला, प्र.मंत्री के रूप में, वे मानते हैं, उन्हें भी मिलना चाहिए।
- वे यह भी मान रहे हैं कि उनका ''कास्ट कार्ड'' उन्हें प्र.मंत्री पद तक पहुँचायेगा और उनकी प्र.मंत्री की कुर्सी तक की पद यात्रा अब आसान भी हो गई है, क्योंकि मोदी कमज़ोर पड़े हैं, भाजपा व संघ के मतभेदों के कारण तथा नीतीश कुमार की बीमारी व शारीरिक कमज़ोरी के कारण, वे बिहार में जरूर जीतेंगे। साथ ही अमेरिका व ट्रंप अब मोदी का उतना समर्थन नहीं कर रहे, जो पहले करते थे।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जून। राहुल गांधी अब वह अनिच्छुक राजनीतिज्ञ नहीं रहे, जैसा उन्हें वर्षों तक बताया जाता रहा है।

कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि अब वह स्वयं को देश के सर्वोच्च पद के लिए तैयार मानते हैं। इससे भी अधिक, अब वह भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्सुक और इच्छुक हैं।

यह परिवर्तन विपक्ष के नेता बनने के बाद आया जब उन्होंने इस पद के साथ आने वाली सत्ता और प्रभाव का अनुभव किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारों ओर व्याप्त सत्ता की ताकत, पद और प्रतिष्ठा ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया है।

राहुल गांधी का जन्मदिन पार्टी के कई लोगों के लिए आंखें खोलने वाला रहा और अब कांग्रेस के भीतर यह चर्चा ज़ोर पकड़ रही है कि राहुल अब प्रधानमंत्री पद की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं।

राहुल गांधी के लिए उनका जन्मदिन हमेशा एक निजी मामला रहा है। वह अक्सर 19 जून को देश से बाहर रहते थे, न ही कांग्रेसजनों से मिलते थे और न ही शुभकामनाएं देने आने वाली भीड़ से।

इस बार सब कुछ बिल्कुल अलग था, जिसने सभी का ध्यान खींचा।

अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वह दिल्ली लौटे।

यह वापसी उनकी मां सोनिया गांधी की तबीयत के कारण नहीं थी, क्योंकि उन्हें उसी सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और राहुल उन्हें घर लाने गए थे।

अप्रत्याशित रूप से वह 24 अकबर रोड स्थित एआईसीसी कार्यालय पहुंचे। उनके आने से पहले संदेश दिया गया था कि वह दोपहर 2 बजे वहां आएंगे। उन्होंने वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विशाखापट्टनम में योग करेंगे प्र.मंत्री

नयी दिल्ली, 20 जून। देश और दुनिया भर में कल 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जायेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सामूहिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे तीन लाख से अधिक लोगों के साथ योगासन करेंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग संगम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तीन लाख लोगों के साथ योग करेंगे। देश भर में दस लाख से अधिक स्थानों पर योग संगम से तालमेल कर योगाभ्यास किया जाएगा।

जाधव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे।

विशाखापत्तनम में आयोजित इस कार्यक्रम में 'योग संगम' पहल के तहत देश भर में 10 लाख से अधिक स्थानों के साथ एक साथ योग किया जाएगा।

यह कार्यक्रम सुबह साढे छह बजे शुरू होगा और पौने आठ बजे संपन्न होगा। इसमें देश भर से अभूतपूर्व भागीदारी की उम्मीद है। देश में विभिन्न जगहों पर आयोजत सत्रों में दो करोड़

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईडी ने वरिष्ठ अधिवक्ता वेणुगोपाल को भेजे गए सम्मन को रद्द किया

सम्मन भेजने का कारण था, वेणुगोपाल द्वारा अपने ''क्लाइंट'' को दी गई कानूनी सलाह

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जून। नवीनतम घटनाक्रम के तहत एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) प्रवर्तन निदेशालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रताप वेणुगोपाल को दिया गया समन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। यह समन उनके द्वारा एक क्लाइंट को दी गई कानूनी सलाह के संबंध में जारी किया गया था।

गौरतलब है कि, 18 जून को ईडी ने वेणुगोपाल को समन जारी किया था, जो एम/एस केयर हेल्थ इंश्योरेंस को एम्प्लॉयी स्टॉक ओनरशिप प्लान (ईएसओपी) के संबंध में दी गई कानूनी सलाह के विषय में था। यह ईएसओपी पूर्व रिलिगेयर एंटरप्राइजेज की अध्यक्ष डॉ. रश्मि सलूजा को जारी किया गया था। इससे पहले, इसी तरह के समन वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को भी जारी किए गए थे, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भारत के मुख्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इसी प्रकार के सम्मन वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को भी भेजे गये थे, पर, फिर ईडी को उस सम्मन को भी वापस लेना पड़ा था।
- सुप्रीम कोर्ट की ''एडवोकेट्स-ऑन रिकॉर्ड'' की एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा, जिसमें ईडी द्वारा वरिष्ठ व प्रतिष्ठित अधिवक्ता वेणुगोपाल को भेजे गये सम्मन की निंदा की। पत्र में यह लिखा था कि ईडी द्वारा सम्मन भेजने की कार्यवाही का ''व्यापक'' दुष्प्रभाव पड़ेगा, कानूनी कार्यवाही की निर्भयता से अपनी कानूनी राय देने के अधिकार पर'' तथा ''क्लाइंट व वकील'' के विश्वास के रिश्ते की नींव हिल जायेगी।
- ईडी के सहायक निदेशक (मुम्बई) ने तुरंत प्रभाव से सम्मन को वापस लिया।
- एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एसोसिएशन ने पत्र में यह भी मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट ''गाइडलाइन'' बनाये, जिससे ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं की, उनके अपने ''क्लाइंट'' को दी गई सलाह को आधार बनाकर वकीलों को सम्मन भेजने की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति न हो।

'आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा हटाने के लिए संविधान संशोधन लाया जाए'

कांग्रेस ने कहा कि आगामी मानसून सत्र में वह जोर-शोर से यह मांग उठाएगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जून। कांग्रेस ने शुक्रवार को बिहार आरक्षण कानून को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने, आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा हटाने के लिए संविधान में संशोधन करने और अनुच्छेद 15(5) को लागू करने की अपनी मांग दोहराई, जो निजी शैक्षिणक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईबीसी को आरक्षण प्रदान करता है।

पार्टी के महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी इन तीन महत्वपूर्ण मुद्दों को आगामी मानसून सत्र में संसद में उठाएगी, जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

जयराम रमेश ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री शुक्रवार को बिहार गए। बिहार में हैं। पूर्व की इंडिया गठबंधन सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण के आधार पर, बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईबीसी के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण प्रस्तावित किया था। यह प्रस्ताव वर्तमान में न्यायालयों विचाराधीन है।

उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार लगभग हार मान चुकी है।

उन्होंने आगे कहा, लेकिन कांग्रेस लंबे समय से जो तीन माँगे कर रही है, वे 65 प्रतिशत आरक्षण को हकीकत बना सकती हैं।

जयराम रमेश ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान की नवीं अनुसूची

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, जयराम रमेश ने यह भी बताया कि बिहार की इंडिया ब्लॉक सरकार ने कास्ट सर्वे के बाद जो विधेयक पारित किए थे और जिन्हें अदालत में चुनौती दी गई है, उन्हें संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी।
- कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन के क्रियान्वयन की मांग भी उठाएगी। डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लाया गया यह संविधान संशोधन 11 साल से ठंडे बस्ते में है।

एक्सिओम मिशन -4 फिर से स्थगित

चेन्नई, 20 जून। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा पर ले जाने वाले एक्सिओम-4 मिशन को फिर से स्थगित कर दिया गया है। यह मिशन 22 जून को निर्धारित था।

एक्सिओम स्पेस ने शुक्रवार को

- भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभाशुं को अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाला यह मिशन 22 जून को निर्धारित था

एक नवीनतम अपडेट में कहा कि नई लॉन्च तिथि की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। मिशन शुरू में 29 मई के लिए निर्धारित किया गया था। मिशन को मौसम, एलओएक्स रिसाव और अन्य तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से इसे कई बार स्थगित किया है। इस मिशन में आईएसएस में अंतरिक्ष यात्रियों को 14 दिनों तक रहना है और इस अवधि में वे वहां पर 60 अनुसंधान करेंगे। इनमें से सात माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान इसरो के हैं। भारत, अमेरिका, हंगरी और पोलैंड की चार अंतरिक्षयात्रियों की टीम अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए तैयार है।

इज़रायल खुशी मना रहा है, ईरान की हवाई युद्ध लड़ने की ताकत पर पूरी तरह छा कर

पर, विश्व इस प्रमुख ऑयल इण्डस्ट्री पर कुप्रभाव की कल्पना करके कांप रहा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जून। पिछले दो हफ्तों में अपने व्यापक हवाई अभियान के जरिए, इज़रायल ने वह हासिल कर लिया है जिसे कई लोग असंभव मानते थे: ईरान का 90 प्रतिशत लाँगरेंज एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय कर दिया है और लगभग आधी मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता को बेअसर कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तेल अवीव इस सैन्य सफलता का जश्न मना रहा है, वहीं दुनिया एक और खतरे के लिए तैयार हो रही है, एक अस्थिर मिडिल ईस्ट और आसमान छूती तेल की कीमतें, जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को झटका दे सकती हैं।

इज़रायली हवाई हमलों की पहली लहर के साथ ही तेल बाज़ारों में तुरंत प्रतिक्रिया देखी गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गई। यह उछाल सिर्फ ईरानी तेल निर्यात में रुकावट के कारण नहीं है, जो पहले से ही प्रतिबंधों के तहत है, बल्कि यह भविष्य को लेकर गहराते भय का संकेत है। ईरान ने होरमुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होरमुज़) को बंद करने की धमकी दी है, जो एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है और जहाँ से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल गुज़रता है। हालाँकि, यह मार्ग अभी खुला है, लेकिन टैंकर यातायात काफी धीमा हो गया है, और कुछ मामलों में जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के जरिए लंबा और महँगा रास्ता लेना पड़ा है।

इस चिंता को खाड़ी क्षेत्र से होकर गुज़रने वाले जहाज़ों के लिए बीमा प्रीमियम में अचानक हुई वृद्धि ने और बढ़ा दिया है।कई प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र में परिचालन रोक दिया है, और तेल कंपनियाँ डिलीवरी में देरी की सूचना दे रही हैं। इसके जवाब में, अमेरिका, भारत और चीन अपने रणनीतिक तेल भंडार से तेल जारी करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि, स्थिति को कुछ समय के लिए संभाला जा सके। लेकिन ये उपाय केवल अस्थायी राहत दे सकते हैं। अगर सैन्य संघर्ष और तेज़ हुआ, या फिर, ईरान समर्थित लड़ाकों ने सऊदी अरब या यूएई के तेल ढांचों पर हमला किया तो दुनिया एक गंभीर आपूर्ति संकट का सामना कर सकती है।

रणनीतिक परिणाम भी उतने ही चिंताजनक है। इज़रायल ने ईरान का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कई ऑयल कम्पनियों ने अपने टैंकर्स में ''स्ट्रेट ऑफ होरमुज़'' में जाने से रोक दिए हैं तथा ऑयल के दाम कुछ दिनों में ही 90 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 105 डॉलर प्रति बैरल हो गये हैं।
- इसके अलावा इंश्योरैंस कम्पनियों ने इन टैंकर्स को इन्श्योर करने की कीमत में भी भारी वृद्धि कर दी है।
- साथ ही, यमन हाउथीस, लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे समुद्री लुटेरों व आतंकवादियों ने ईरान के कमज़ोर पड़ जाने के बाद अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं।
- सभी आशंकित हैं, यह अनिश्चितता क्या कहर ढायेगी। इसका अंदाज़ा लगाना ही कठिन है।

विमान हादसा: 223 मृतकों के डीएनए सैंपल मैच हुए

अहमदाबाद, 20 जून। गुजरात के अहमदाबाद में हाल में हुए विमान हादसे में मारे गए 223 लोगों के डीएनए सैंपल का मिलान हो गया है तथा अब तक 204 मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं।

- अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक राकेश जोशी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि 204 शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं।

अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने शुक्रवार को कहा कि 220 रिश्तेदारों से संपर्क किया गया है। सिविल अस्पताल में उपचाराधीन दो व्यक्तियों के शव भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या वियतनाम, अफगानिस्तान, क्यूबा और ईरान के असफल प्रयासों से कुछ नहीं सीखा अमेरिका ने?

हर बार अमेरिका असफल हुआ तथा ''अग्ली अमेरिकन'' की छवि पाई, जो अब तक पूरी तरह नहीं बदल पाई है

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 20 जून। अमेरिका ने वियतनाम, अफगानिस्तान और उससे भी पहले ईरान में मिली नाकामियों से कोई सबक सीखा है या नहीं- यह चीज राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के इस कदम से तय होगी कि वे अपने सहयोगी इज़राइल और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष में अमेरिका को झोंकने का फैसला करते हैं या नहीं।

जब यह रिपोर्ट लिखी जा रही थी, तब तक ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि अमेरिका आधिकारिक रूप से इज़राइल के युद्ध में शामिल होगा या नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि वियतनाम, अफगानिस्तान, क्यूबा और यहां तक कि ईरान में भी अमेरिका की दखलअंदाजी ने उलटा असर डाला और अमेरिका की छवि ''अहंकारी अमेरिकी'' (अगली अमेरिकन) के रूप में उभरी। फिलहाल वॉशिंगटन युद्ध की तैयारियों को अंतिम रूप देता दिखाई दे रहा है - यह कोई दिखावे की चाल है या असली योजना, इसका पता जल्द ही चल जाएगा। पिछली बार जब अमेरिका ने तेहरान में तख्ता पलट किया था, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं रहा था।

ईरान और पश्चिम के बीच तनाव का इतिहास एक निर्णायक घटना से जुड़ा है, सन् 1953 में ईरान में अमेरिकी सीआईए और ब्रिटिश एमआई6 द्वारा समर्थित तख्तापलट हुआ था, जिसमें ईरान के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देग को हटा कर, शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को सत्ता में वापस लाया गया था और राजशाही की बहाली की गई थी। अजीब विरोधाभास था, दो लोकतांत्रिक सरकारों-अमेरिका और ब्रिटेन-ने एक निर्वाचित सरकार को गिरा कर राजतंत्र बहाल किया- और उसे अपनी जनता के सामने विजय के रूप में प्रस्तुत किया।

ईरान की रणनीतिक स्थिति और विशाल तेल भंडार इसे वैश्विक शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन, के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ब्रिटेन ने ईरान में अपनी एक मजबूत उपस्थिति बनाई, ताकि वह सोवियत संघ (जो उस समय उसका सहयोगी था) तक तेल की आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित कर सके और हिटलर के द्वारा शासित जर्मनी को क्षेत्र के तेल संसाधनों से दूर रखा जा सके।

युद्ध के बाद भी ब्रिटिश प्रभाव बना रहा, खासकर - ऐंग्लो-ईरानियन ऑयल कंपनी जो अब ब्रिटिश पेट्रोलियम का हिस्सा है) के माध्यम से। यह व्यवस्था 1951 में उस समय टूटी, जब मोसद्देग के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक सरकार ने ईरान की संसद के जरिए तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

यह निर्णय ईरान के संसाधनों की पुनः प्राप्ति के रूप में तो देखा गया,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अमेरिका के सी.आई.ए. व ब्रिटेन की इंटैलिज़ैंस एजेंसी एम.आई.सिक्स ने इन प्रयासों की शुरुआत 1953 में ही कर दी थी। प्रजातंत्रीय तरीके से चुनी गई प्र.मंत्री मोहम्मद मोसद्देग की सरकार को अपदस्थ करके, शाहे मोहम्मद रिज़ा पहलवी को पुनः गद्दी पर स्थापित करके।
- चुनी गई सरकार को अपदस्थ करने का प्रमुख कारण था, ईरान की जमीन के नीचे ऑयल का अपार भंडार।
- यह ही कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के हाथों में ''ऑयल भंडार'' न पहुँचे, इसे रोकने के लिए अमेरिका व ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन के लिए एक ''सप्लाई कोरिडोर'' बनाया था।
- पर, 1951 में मोसद्देग की निर्वाचित सरकार ने संसद में विधेयक पास कर, ईरान की ऑयल इण्डस्ट्री का नैशलनाइज़ेशन कर, अमेरिका व ब्रिटेन की योजना को फेल कर दिया था।

पासपोर्ट आवेदन के लिए पति के हस्ताक्षर की जरुरत नहीं

चेन्नई, 20 जून। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले अपने पति की अनुमति लेने या उसके हस्ताक्षर करवाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने यह फैसला हाल ही

- मद्रास हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता रेवती की याचिका पर यह फैसला दिया और पासपोर्ट कार्यालय को पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया।

में रेवती नाम की महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। रेवती ने अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे उनके पति के हस्ताक्षर की अनिवार्यता के बिना ही एक नया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)